

अध्याय 03

शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

Education and the Knowledge Economy — राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 (मूल अंग्रेज़ी संस्करण से सत्यापित)

शुरुआत एक कहानी से

सोचिए — आज़ादी के समय राजस्थान में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 कॉलेज थे। आज यह संख्या बढ़कर 3,218 हो चुकी है! एक राज्य जहाँ कभी शिक्षा तक पहुँच सबसे बड़ी चुनौती थी, वहाँ आज 49 मेडिकल कॉलेज, 1 IIT, 1 IIM और हज़ारों स्कूल हैं।

शिक्षा को राजस्थान सरकार **मानव संसाधन विकास का सबसे बड़ा निवेश** मानती है — क्योंकि शिक्षा ही वह कड़ी है जो गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता को तोड़ती है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे — स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी तक — राजस्थान की पूरी "ज्ञान अर्थव्यवस्था" कैसे आकार ले रही है।

विषय-सूची

- | | |
|--|---|
| 01. विज्ञान : विकसित राजस्थान @2047 — शिक्षा | 06. साक्षरता एवं सतत शिक्षा (Literacy & Continuing Education) |
| 02. स्कूली शिक्षा — प्रारंभिक व माध्यमिक (आँकड़े व 5 सांख्यिकीय संकेतक) | 07. उच्च शिक्षा — कॉलेज, बालिका-केंद्रित योजनाएँ, PM Usha/RUSA |
| 03. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha) — A से J तक 10 स्तंभ | 08. तकनीकी शिक्षा — इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI |
| 04. स्कूली शिक्षा की प्रमुख योजनाएँ (छात्रवृत्ति, निःशुल्क सुविधाएँ) | 09. चिकित्सा शिक्षा — मेडिकल व डेंटल कॉलेज |
| 05. शिक्षा नीति व मॉडल स्कूल कार्यक्रम (NEP 2020, PM SHRI, MSRA) | 10. संस्कृत शिक्षा, भाषा-पुस्तकालय एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी |

विज्ञान वक्तव्य — विकसित राजस्थान @2047

2047 का लक्ष्य

2047 तक राजस्थान में **विद्यार्थी-केंद्रित, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित** शिक्षण प्रणाली होगी, जो पहुँच, समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगी। स्कूली व तकनीकी शिक्षा क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता व बहुविषयी शिक्षण को बढ़ावा देगी। संस्कृत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा और एक जीवंत विज्ञान-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र राजस्थान को ज्ञान व नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाएगा।

🎯 शिक्षा क्षेत्र के 10 फोकस क्षेत्र (Thrust Areas)

फोकस क्षेत्र (क्र. 1-5)	फोकस क्षेत्र (क्र. 6-10)
समावेशी व उच्च-गुणवत्ता शिक्षा	उद्योग-अकादमिक सहयोग
शिक्षक सशक्तिकरण	शोध व नवाचार केंद्र
स्मार्ट अवसंरचना	सततता व आपदा-तैयारी
डिजिटल परिवर्तन	सामुदायिक सहभागिता
करियर व कौशल विकास	वैश्विक पहुँच (Global Outreach)

🏠 स्कूली शिक्षा — प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा सबके लिए

स्कूली शिक्षा बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास की नींव रखती है। यह **प्रारंभिक शिक्षा (Elementary)** व **माध्यमिक शिक्षा (Secondary)** दोनों को समाहित करती है — पहले चरण में बुनियादी ज्ञान, दूसरे चरण में उन्नत विषय व क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।

 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय 44,934 राजकीय विद्यालय	 उच्च माध्यमिक विद्यालय 19,950 इनमें 1,364 बालिका विद्यालय	 कुल नामांकन 72.93 लाख राजकीय विद्यालयों में	 उत्कृष्ट विद्यालय 8,373 1,575 प्राथमिक + 6,798 उच्च प्राथमिक
--	---	---	--

- ▶ प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को **उत्कृष्ट विद्यालय योजना** के तहत चुनकर विकसित किया जा रहा है।
- ▶ 2025-26 में **3,737 महात्मा गाँधी विद्यालय (अंग्रेज़ी माध्यम)** संचालित हैं जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं — इनमें से 977 स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएँ व 1,010 बाल वाटिकाएँ भी चल रही हैं।
- ▶ प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु **एक भारत श्रेष्ठ भारत, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PARAKH National Survey)**, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति व निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जैसी प्रमुख पहलें साथ-साथ लागू हैं।

📊 छात्र-शिक्षक अनुपात (2025-26)

 प्राथमिक शिक्षा 13 : 1 नामांकन 22.72 लाख, शिक्षक 1.69 लाख	 माध्यमिक शिक्षा 18 : 1 नामांकन 50.22 लाख, शिक्षक 2.82 लाख
---	---

💡 याद रखें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अनुशंसित अनुपात **30:1** है — राजस्थान के दोनों अनुपात (13:1 व 18:1) इससे बेहतर व कहीं अधिक सुविधाजनक हैं।

5 प्रमुख शैक्षिक सांख्यिकीय संकेतक — सरल समझ

स्कूली शिक्षा की प्रगति मापने के लिए 5 प्रमुख संकेतक उपयोग होते हैं — इन्हें उदाहरण सहित समझें ताकि आगे की तालिकाएँ आसानी से समझ आएँ:

सकल नामांकन अनुपात (GER — Gross Enrolment Ratio)

परिभाषा : किसी शिक्षा स्तर में कुल नामांकन (आयु चाहे जो भी हो), उस स्तर की आधिकारिक आयु-समूह जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में

आसान भाषा में : यानी स्कूल में कितने % बच्चे भर्ती हैं — भले ही उनकी उम्र सही कक्षा से थोड़ी कम/ज़्यादा हो।

उदाहरण : उदाहरण : यदि किसी इलाके में प्राथमिक (कक्षा 1-5) आयु-वर्ग के 100 बच्चे हैं, पर स्कूल में कुल 88 बच्चे नामांकित हैं (चाहे उम्र में थोड़ा आगे-पीछे भी हों) — तो $GER = 88\%$ । 2024-25 में राजस्थान का प्राथमिक GER 88.3% रहा।

छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR — Pupil Teacher Ratio)

परिभाषा : किसी शिक्षा स्तर पर प्रति शिक्षक औसत विद्यार्थियों की संख्या

आसान भाषा में : यानी एक शिक्षक को औसतन कितने बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं।

उदाहरण : उदाहरण : यदि किसी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 1,500 विद्यार्थी और 100 शिक्षक हैं, तो $PTR = 15:1$ । 2024-25 में राजस्थान का उच्च माध्यमिक PTR भी ठीक 15 रहा।

संक्रमण दर (Transition Rate)

परिभाषा : एक शिक्षा स्तर की अंतिम कक्षा से अगले स्तर की पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों का अनुपात

आसान भाषा में : यानी कक्षा 8 पास करने वाले कितने बच्चे कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं।

उदाहरण : उदाहरण : यदि कक्षा 8 में 100 बच्चे थे और अगले साल उनमें से 90 बच्चों ने कक्षा 9 में प्रवेश लिया, तो संक्रमण दर = 90%। 2024-25 में उच्च प्राथमिक→माध्यमिक संक्रमण दर 90.2% रही।

— ACADEMY —

ठहराव दर (Retention Rate)

परिभाषा : किसी स्तर की पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के समूह में से कितने % उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुँचने की संभावना रखते हैं

आसान भाषा में : यानी जो बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए, उनमें से कितने % बीच में स्कूल छोड़े बिना अंतिम कक्षा तक टिके रहते हैं।

उदाहरण : उदाहरण : यदि कक्षा 1 में 100 बच्चे भर्ती हुए और उनमें से 78 बच्चे कक्षा 8 तक पहुँचे, तो प्रारंभिक ठहराव दर = 78%। 2024-25 में राजस्थान की प्रारंभिक (1-8) ठहराव दर 78.7% रही।

अवसान/ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate)

परिभाषा : किसी स्तर में नामांकित विद्यार्थियों के समूह में से जो अगले शैक्षणिक वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं रहते

आसान भाषा में : यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत।

उदाहरण : उदाहरण : यदि माध्यमिक स्तर पर 100 बच्चों में से 8 बच्चे अगले साल स्कूल में नहीं दिखे, तो ड्रॉपआउट दर = 8%। 2024-25 में राजस्थान की माध्यमिक ड्रॉपआउट दर 7.7% रही — 2023-24 के 11.1% से बेहतर सुधार।

तालिका 3.1 : सकल नामांकन अनुपात (GER) — राजस्थान

वर्ष	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	प्रारंभिक (1-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
2023-24	95.1	90.9	93.6	80.2	62.0
2024-25	88.3	92.1	89.7	82.2	66.1

- 2024-25 में प्राथमिक GER में 6.8 प्रतिशत बिंदु की गिरावट दर्ज हुई, जबकि उच्च प्राथमिक (+1.2) व उच्च माध्यमिक (+4.1) में सुधार हुआ।

स्रोत : Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2023-24, 2024-25, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका 3.2, 3.3 : PTR एवं संक्रमण दर (2024-25)

संकेतक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक/संक्रमण	उच्च माध्यमिक
छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)	18	12	11	15
संक्रमण दर (%) — क्रमशः 5→6, 8→9, 10→11	—	93.8	90.2	88.2

तालिका 3.4, 3.5 : ठहराव दर एवं ड्रॉपआउट दर

संकेतक	प्राथमिक	प्रारंभिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
ठहराव दर 2023-24 (%)	82.5	75.3	59.1	48.9
ठहराव दर 2024-25 (%)	83.1	78.7	55.9	51.9
ड्रॉपआउट दर 2023-24 (%)	7.6	6.8	11.1	—
ड्रॉपआउट दर 2024-25 (%)	3.6	3.6	7.7	—

⚠ ध्यान देने योग्य बिंदु

माध्यमिक स्तर पर ठहराव दर में गिरावट (59.1% → 55.9%) चिंताजनक संकेत है, जबकि बाकी सभी स्तरों पर सुधार हुआ — यह दर्शाता है कि कक्षा 9-10 के बाद बच्चों को स्कूल में टिकाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है।

फिर भी माध्यमिक स्तर की ड्रॉपआउट दर 11.1% से घटकर 7.7% हो गई — यानी स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति घट रही है, भले ही अंतिम कक्षा तक पहुँचने की दर धीमी हो।

\$ स्कूली शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएँ (2025-26, दिसंबर तक)

वंचित व पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु कई छात्रवृत्ति योजनाएँ स्कूली शिक्षा में समांतर रूप से चलती हैं:

शिक्षा स्तर	पात्र श्रेणियाँ (Categories)	लाभार्थी व व्यय
माध्यमिक शिक्षा	सफाई/स्वास्थ्य-जोखिम व्यवसाय (Scavenger) परिवारों के बच्चे, अति पिछड़ा वर्ग (प्री+पोस्ट मैट्रिक), अनुसूचित जाति (प्री+पोस्ट), अनुसूचित जनजाति (प्री+पोस्ट), अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 9-10 प्री-मैट्रिक), देवनारायण गुरुकुल (विशेष प्री-मैट्रिक, MBC)	2.93 लाख विद्यार्थी लाभान्वित; ₹67.50 करोड़ व्यय
प्रारंभिक शिक्षा	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग व स्वच्छता/स्वास्थ्य-जोखिम व्यवसाय में लगे अभिभावकों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	₹20.04 करोड़ व्यय

💡 ज्ञान संकल्प पोर्टल — CSR से स्कूलों की मदद

ज्ञान संकल्प पोर्टल — दानदाताओं/भामाशाहों/कंपनियों (CSR के तहत) से राजकीय स्कूलों के विकास कार्यों हेतु सीधा योगदान लेने का ऑनलाइन मंच — 2025-26 में ₹34.38 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत (दिसंबर तक)।

29वाँ राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह (2025) में **135 भामाशाह व 91 प्रेरक** सम्मानित हुए — इनका कुल शिक्षा-योगदान ₹139.90 करोड़ रहा।

समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha)

📖 समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha)

परिभाषा : एक केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्र:राज्य = 60:40) जो प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है — सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक-शिक्षा योजनाओं का एकीकरण

💡 **आसान भाषा में :** यानी पहले जो 3 अलग-अलग योजनाएँ (प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए) अलग-अलग चलती थीं, अब वे सब एक ही "समग्र शिक्षा" छाते के नीचे एक साथ चलती हैं — जैसे एक ही थाली में सारे व्यंजन।

🏠 **उदाहरण :** राजस्थान में इसे **राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद** एकल राज्य कार्यान्वयन समिति के रूप में लागू करती है — इसके 10 स्तंभ (A-J) नीचे दिए गए हैं।

New India Education by Omkar Sir

A. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा (ECCE)

- ▶ 62,000 आँगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 वर्ष आयु-वर्ग के **11.90 लाख बच्चे** पूर्व-विद्यालय शिक्षा का लाभ ले रहे हैं — इनमें से 42,554 AWCs स्कूलों से एकीकृत हैं (22,746 भौतिक रूप से परिसर में, 19,808 कार्यात्मक रूप से 700 मीटर की दूरी में)।
- ▶ 962 बाल वाटिकाएँ महात्मा गाँधी (अंग्रेज़ी माध्यम) स्कूलों में व 629 बाल वाटिकाएँ PM SHRI स्कूलों में संचालित।

B. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा

📖 निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat — FLN)

परिभाषा : कक्षा 1-5 के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) प्रदान करने का राष्ट्रीय मिशन, लक्ष्य 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ना-लिखना सीख जाए

💡 **आसान भाषा में :** यानी छोटी कक्षाओं में बच्चों को ठीक से पढ़ना-लिखना व गिनती सिखाने पर ज़ोर, ताकि आगे की पढ़ाई की नींव मज़बूत हो।

🏠 **उदाहरण :** "निपुण मेला" पंचायत स्तर पर आयोजित होते हैं, कक्षा 1 के लिए "विद्या प्रवेश" व कक्षा 3-5 के लिए विषय-वार वर्कबुक दी जाती हैं। इससे 35.41 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए, ₹50.09 करोड़ खर्च हुआ (2025-26, दिसंबर तक)।

- ▶ **शिक्षक संसाधन एवं सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE)** — कक्षा 1-5 के शिक्षकों को बाल-केंद्रित शिक्षण हेतु गतिविधि पुस्तिकाएँ व CCE सामग्री दी जाती है; राज्य/ज़िला/ब्लॉक शैक्षणिक कार्यबल (SATF/DATF/BATF) व FLN सलाहकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा तिमाही क्लस्टर-स्तरीय कार्यशालाएँ आयोजित होती हैं — शिक्षक प्रशिक्षण हेतु NCERT की **NISHTA** पहल भी इसी दिशा में सहायक है।
- ▶ **प्रखर राजस्थान 2.0** — पठन कौशल मज़बूत करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत राज्य-स्तरीय कार्यक्रम।
- ▶ **निपुण राजस्थान अभियान** — 30 अक्टूबर 2025 से कक्षा 1-2 के लिए शुरू; **PRABAL कार्यक्रम** — कक्षा 9-12 के किशोरों में 21वीं सदी के जीवन-कौशल, नेतृत्व व करियर-कौशल विकसित करने हेतु।
- ▶ **मेगा PTM** — 31 अक्टूबर 2025 (राष्ट्रीय एकता दिवस) को सभी स्कूलों में आयोजित; अभिभावकों से बच्चों की पठन-प्रगति साझा की गई।

C. पहुँच एवं ठहराव (Access and Retention)

निम्न प्रमुख योजनाएँ बालक-बालिकाओं की पहुँच व ठहराव सुनिश्चित करती हैं:

1. स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल	
📅 सतत/जारी कार्यक्रम 🏠 राज्य योजना	
उद्देश्य	शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (EBB) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा — बालिका शिक्षा पर विशेष ज़ोर (न्यूनतम 55% सीटें आरक्षित)
संबद्धता	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली — पाठ्यक्रम NCERT आधारित
कवरेज	27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 स्कूल; 62,433 विद्यार्थी नामांकित (2025-26, दिसंबर तक)

2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावास	
📅 सतत/जारी कार्यक्रम 🏠 राज्य योजना	
संरचना	10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय + 20 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास + 11 बेघर-बेसहारा व अनाथ श्रेणी विद्यालय/छात्रावास (कुल 41)
क्षमता एवं नामांकन	3,900 प्रवेश क्षमता में से 3,458 बालिकाएँ नामांकित (2025-26, दिसंबर तक)
वित्त	शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ₹20.94 करोड़ में से ₹16.76 करोड़ ज़िलों को आवंटित

- ▶ **परिवहन वाउचर** — कक्षा 1-5 के लिए 1 किमी, कक्षा 6-8 के लिए 2 किमी से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को; कक्षा 9-10 की बालिकाओं को 5 किमी से दूर रहने पर — स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वितरित; ₹187.72 करोड़ आवंटित।

📖 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009

📖 **परिभाषा** : 1 अप्रैल 2010 से लागू — निजी स्कूलों में कमज़ोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य

💡 **आसान भाषा में** : यानी हर निजी स्कूल को अपनी कुल सीटों में से एक-चौथाई सीटें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में देनी होती हैं।

🏠 **उदाहरण** : आय पात्रता सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख कर दी गई। 2024-25 में निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति हेतु ₹546.13 करोड़ स्वीकृत।

D. शिक्षा में अवसंरचना विकास

- ▶ प्रारंभिक शिक्षा (SMSA) के तहत कक्षा-कक्षा, शौचालय, पेयजल, KGBV भवन आदि के लिए ₹348.64 करोड़ लक्ष्य; ₹93.62 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।
- ▶ माध्यमिक शिक्षा (SMSA) के तहत विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम, पुस्तकालय, CWSN शौचालय आदि के लिए ₹1,420.08 करोड़ लक्ष्य; ₹205.42 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।

E. गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप

3. निःशुल्क यूनिफॉर्म व पाठ्यपुस्तक वितरण

🏆 प्रतियोगिता योजना | 🏠 राज्य योजना

यूनिफॉर्म (2025-26)	कक्षा 1-8 के सभी विद्यार्थियों को ₹600 प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से
यूनिफॉर्म (2024-25)	कक्षा 1-8 व कक्षा 9-12 की बालिकाओं को ₹800/विद्यार्थी (सिलाई+बैग सहित); ₹330.06 करोड़ खर्च, 41.26 लाख लाभान्वित
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	कक्षा 1-8 सभी, कक्षा 9-12 सभी बालिकाएँ, SC/ST विद्यार्थी, गैर-आयकरदाता अभिभावकों के बच्चे — 2025-26 में 4.05 करोड़ पुस्तकें, 80 लाख विद्यार्थियों को
निःशुल्क साइकिल	कक्षा 9 की सभी बालिकाओं को — 2024-25 में 3.25 लाख साइकिलें वितरित; 2025-26 के लिए 3.34 लाख का आपूर्ति आदेश

4. PM SHRI स्कूल योजना

🏆 प्रतियोगिता योजना | 🇮🇳 केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम

शुरुआत	2022 — मौजूदा स्कूलों को हरित, डिजिटल व नवाचार-आधारित मॉडल स्कूल के रूप में सुदृढ़ करना
हरित सुविधाएँ	सोलर पैनल, LED लाइटिंग, न्यूट्रिशन गार्डन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक-मुक्त परिसर, जल संरक्षण
राजस्थान में कवरेज	639 स्कूल (90 प्रारंभिक + 549 माध्यमिक + 1 संस्कृत शिक्षा); 2.96 लाख विद्यार्थी; ₹51.81 करोड़ खर्च (प्रावधान ₹434.65 करोड़)

📖 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 व SARTHAQ

📖 **परिभाषा** : 29 जुलाई 2020 को शुरू हुई शिक्षा नीति; इसे लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने SARTHAQ (Students And Teachers Holistic Advancement through Quality Education) पहल के तहत 27 अध्यायों में 297 कार्य निर्धारित किए

💡 **आसान भाषा में** : यानी एक बड़ा राष्ट्रीय एक्शन-प्लान जो बताता है कि NEP को ज़मीन पर कैसे लागू करना है — किसे, कब, क्या करना है।

🏠 **उदाहरण** : 297 में से 202 कार्य राज्यों को सौंपे गए, जिनमें से राजस्थान ने दिसंबर 2025 तक 73 कार्य पूरे किए — 6 समितियों व ज़िला कलेक्टर-अध्यक्षता वाली ज़िला-स्तरीय समितियों के माध्यम से, गूगल "202 टास्क ट्रैकर" से मासिक निगरानी।

5. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)

🏆 प्रतियोगिता योजना | 🏠 राज्य योजना

उद्देश्य	राजस्थान में NEP 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करना — राज्य को मॉडल बनाना, नामांकन व गुणवत्ता बढ़ाना
----------	--

रणनीति	NEP बालक, NEP शिक्षक व NEP स्कूल — तीन बहुवर्षीय कार्यक्रमों के रूप में लागू
गतिविधियाँ (29 अप्रैल 2025 से)	राज्य-स्तरीय AI-आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF) मूल्यांकन, छात्र उपस्थिति ऐप, NIOS हेतु ऑन-डिमांड परीक्षाएँ, डिजिटल पहलें

6. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

 सतत/जारी कार्यक्रम |  राज्य योजना

शुरुआत	बजट 2022-23 — पंजीकृत मदरसों को कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षा, फर्नीचर व ई-लर्निंग उपकरणों से उन्नत करना
वित्तीय सहायता	प्राथमिक स्तर मदरसों को ₹15 लाख तक, उच्च प्राथमिक को ₹25 लाख तक (राज्य 90% + मदरसा प्रबंधन समिति 10%)
लाभार्थी	दिसंबर 2025 तक कुल 305 मदरसे लाभान्वित

- ▶ **कला उत्सव** — कक्षा 9-12 के लिए 6 विधाओं (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, पारंपरिक कहानी) में जिला-राज्य-राष्ट्रीय स्तर की कला प्रतियोगिता; राजस्थान से 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं।
- ▶ 2025-26 में 226 उच्च प्राथमिक व 2 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत; AI-आधारित मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम शुरू; "वीरगाथा 3.0" व राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम (1.53 करोड़ विद्यार्थी) ने विश्व रिकॉर्ड बनाया।

F. लैंगिक समानता (Gender Equality)

- ▶ 2025-26 में **364 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV)** कार्यरत — 44,040 बालिकाएँ नामांकित; कभी-नामांकित-न-हुई व ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्राथमिकता। ₹224.33 करोड़ में से ₹107.38 करोड़ (केंद्र) + ₹8.17 करोड़ (राज्य) जिलों को आवंटित।
- ▶ किशोरी बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम — 628 PM SHRI स्कूलों को ₹14.42 लाख; सुरक्षित स्कूल परिवेश हेतु 639 स्कूलों को ₹6.77 लाख — जिसमें मीना-राजू-गार्गी मंच मॉड्यूल, बाल अधिकार क्लब आदि शामिल।

❤ लाडो प्रोत्साहन योजना — बालिका जन्म से स्नातक तक प्रोत्साहन

लाडो प्रोत्साहन योजना (Lado Protsahan Yojana)

 **परिभाषा :** बालिका के जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण होने तक 7 अलग-अलग पड़ावों पर कुल ₹1.50 लाख तक की प्रोत्साहन राशि माता-पिता/अभिभावक को दी जाती है

 **आसान भाषा में :** यानी बेटी के हर बड़े पड़ाव (जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक) पर सरकार परिवार को पैसा देती है ताकि बेटी को बोझ न समझा जाए और उसकी पढ़ाई बीच में न छूटे।

 **उदाहरण :** किशतें : संस्थागत प्रसव पर ₹2,500 → 1 वर्ष उम्र व पूर्ण टीकाकरण पर ₹2,500 → कक्षा 1 प्रवेश पर ₹4,000 → कक्षा 6 प्रवेश पर ₹5,000 → कक्षा 10 प्रवेश पर ₹11,000 → कक्षा 12 प्रवेश पर ₹25,000 → स्नातक उत्तीर्ण व 21 वर्ष पूर्ण होने पर ₹1 लाख। तीसरी से छठी किशत स्कूल शिक्षा विभाग व सातवीं किशत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। 2025-26 (दिसंबर तक) में ₹18.09 करोड़ व्यय हुआ।

मुख्यमंत्री (D.El.Ed) संबल योजना

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2-वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा (D.El.Ed) करने पर ₹9,000/लाभार्थी शिक्षण-शुल्क सहायता — 2025-26 में प्राप्त 352 ऑनलाइन आवेदनों में से 331 लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित।

G. समावेशी शिक्षा (CWSN)

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs) को मुख्यधारा में लाने हेतु ₹26.07 करोड़ आवंटित, ₹7.30 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।
- जयपुर व उदयपुर में 2 राज्य मॉडल रिसोर्स रूम स्थापित — निःशुल्क चिकित्सकीय व शैक्षिक सेवाएँ।

H. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

- 2025-26 में 4,019 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय 16 क्षेत्रों में संचालित — 3,263 समग्र शिक्षा के तहत (937 द्वि-क्षेत्रीय + 2,326 एकल-क्षेत्रीय), 549 PM SHRI के तहत, 207 STARS प्रोजेक्ट के तहत। 4.70 लाख विद्यार्थी नामांकित; ₹205.33 करोड़ खर्च (आवंटन ₹616.88 करोड़)।

I. ICT एवं डिजिटल पहलें

- 13,976 ICT-लैब सुसज्जित स्कूल व 13,018 स्मार्ट क्लासरूम — e-Gyan/DIKSHA पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा।
- DIKSHA पोर्टल — RSCERT (ET सेल, अजमेर) द्वारा ई-सामग्री अपलोड; मिशन स्टार्ट — विषय-शिक्षक अनुपस्थित होने पर कक्षा 9-12 को डिजिटल सामग्री तक पहुँच; शाला दर्पण — सभी सरकारी स्कूलों व शिक्षा कार्यालयों की लाइव डेटाबेस पोर्टल, परिवहन वाउचर/छात्रवृत्ति/यूनिफॉर्म जैसी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी इसी से होती है।

J. सामुदायिक सहभागिता

- स्कूल प्रबंधन समिति (SMC)/स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के 5 अभिभावक सदस्यों व 1 जन-प्रतिनिधि (कुल 6) को 2-दिवसीय प्रशिक्षण — ₹2.79 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।

साक्षरता एवं सतत शिक्षा (Literacy & Continuing Education)

साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष व अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों (विशेषकर महिलाओं व पिछड़े वर्गों) को कार्यात्मक साक्षरता व उपयोगी कौशल प्रदान करता है।

7. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (ULLAS)

🇮🇳 केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम | 🔄 सतत/जारी कार्यक्रम

शुरुआत	1 अप्रैल 2022 से केंद्र प्रायोजित योजना — 15+ आयु वर्ग में साक्षरता बढ़ाना
क्रियान्वयन	स्वयंसेवी-आधारित अभियान; ULLAS ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सर्वेक्षण
प्रगति (2025-26)	30 लाख के लक्ष्य में से 25.72 लाख निरक्षरों व 1.49 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण; ₹34.37 करोड़ आवंटन में ₹4.24 करोड़ खर्च

- E-साक्षरता व ULLAS राजस्थान यूट्यूब चैनल (8 सितंबर 2023 से) — E-साक्षरता पर 73 वीडियो/27,000+ सब्सक्राइबर, ULLAS राजस्थान पर 18 वीडियो।
- 14,970 महात्मा गाँधी पुस्तकालय व वाचनालय सक्षर भारत कार्यक्रम के तहत संचालित — प्रत्येक को ₹500/माह आवर्ती व्यय।
- पहला FLNAT (Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test) 21 सितंबर 2025 को NIOS के माध्यम से आयोजित — 14.78 लाख शिक्षार्थी उपस्थित।

8. महिला शिक्षण विहार

🏠 राज्य योजना | 🔄 सतत/जारी कार्यक्रम

लाभार्थी	तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूहों की 15-30 वर्ष आयु की महिलाएँ
सुविधा	कक्षा 10 तक शिक्षा + व्यावसायिक प्रशिक्षण, आवासीय स्कूल के रूप में
वर्तमान स्थिति	झालावाड़ ज़िले में संचालित, 100 महिलाएँ नामांकित; ₹29.18 लाख खर्च (दिसंबर तक)

उच्च शिक्षा — ज्ञान-आधारित भविष्य का निर्माण

उच्च शिक्षा व्यक्तियों को व्यावसायिक विकास, आर्थिक प्रगति व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ज्ञान व कौशल से लैस करती है — साथ ही अनुसंधान, नवाचार व सांस्कृतिक संरक्षण को भी बढ़ावा देती है।

 कुल कॉलेज 3,218 आज़ादी के समय केवल 7 थे	 राजकीय कॉलेज 596 +20 विधि +48 कृषि कॉलेज	 निजी कॉलेज 1,589 +957 B.Ed. कॉलेज	 बजट व्यय (2025-26) ₹786.24 करोड़ आवंटन ₹1,552.08 करोड़ में से
---	--	---	---

- 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ — **28 नए राजकीय कॉलेज, 5 नए कृषि कॉलेज, 1 नया विधि कॉलेज** खुले; 5 डिग्री कॉलेज PG में क्रमोन्नत; UG स्तर पर 30 व PG स्तर पर 17 नए विषय शुरू।

बालिका व महिला-केंद्रित उच्च शिक्षा योजनाएँ

योजना	उद्देश्य / लाभ	2025-26 व्यय (दिसंबर तक)
मुख्यमंत्री (B.Ed) संबल योजना	विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को B.Ed. फीस प्रतिपूर्ति	₹31.12 लाख (आवंटन ₹48 लाख)
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं को VMOU/IGNOU ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति	₹20.54 करोड़ (आवंटन ₹21.30 करोड़)
मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना	मेधावी बालिकाओं को वित्तीय सहायता (2015-16 से)	₹91.99 लाख (आवंटन ₹200 लाख)
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	कक्षा 12 पास मेधावी बालिकाओं को स्कूटी	₹67.67 करोड़ (आवंटन ₹299.69 करोड़)
देवनारायण बालिका स्कूटी वितरण योजना (2023 से)	शिक्षा के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण	₹33.71 करोड़ (आवंटन ₹56.10 करोड़)
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	निम्न-आय परिवारों के बच्चों को सहायता	₹21.11 करोड़ (आवंटन ₹45.50 करोड़)

विशेष

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्टता छात्रवृत्ति — Times Higher Education (THE) सूची या NIRF रैंकिंग 1-50 वाले विदेशी/भारतीय संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु; ₹150 करोड़ प्रावधान में से ₹145 करोड़ खर्च (2025-26, दिसंबर तक)।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना — **पात्रता** : कक्षा 12 उत्तीर्ण प्रथम 1 लाख विद्यार्थियों को — सामान्य विद्यार्थी ₹500/माह (वार्षिक ₹5,000), दिव्यांग व अल्पसंख्यक विद्यार्थी ₹1,000/माह (वार्षिक ₹10,000); शर्त — पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम व कोई अन्य छात्रवृत्ति न ली हो।

जनजातीय एवं सहरिया विद्यार्थियों हेतु विशेष वित्तीय सहायता

योजना	2025-26 आवंटन	2025-26 व्यय (दिसंबर तक)
जनजातीय बालिकाओं हेतु उच्च शिक्षा सहायता	₹20 करोड़	₹3.55 करोड़
जनजातीय प्रतिभाशाली बालकों हेतु सहायता (बोर्ड व विश्वविद्यालय)	₹30 लाख	₹7 लाख
सहरिया विद्यार्थी B.Ed प्रशिक्षण सहायता	₹50 लाख	₹31.75 लाख
सहरिया विद्यार्थी उच्च शिक्षा सहायता	₹150 लाख	₹123 लाख

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM Usha)

परिभाषा : केंद्र प्रायोजित योजना (60:40) जो उच्च शिक्षा तंत्र को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक व रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए NEP 2020 के 5 स्तंभों (पहुँच, समानता, जवाबदेही, क्षमता, गुणवत्ता) पर आधारित है

आसान भाषा में : यानी केंद्र व राज्य मिलकर कॉलेजों-विश्वविद्यालयों के भवन, लैब व संसाधन बेहतर बनाने के लिए पैसा देते हैं।

उदाहरण : राजस्थान को RUSA 1.0 में ₹390 करोड़ (110 संस्थान, 94.4% पूर्ण), RUSA 2.0 में ₹221 करोड़ (20 संस्थान, 73.82% पूर्ण) व PM Usha में ₹330 करोड़ (34 संस्थान, 27% पूर्ण) मिले।

नवाचार, कौशल विकास व अवसंरचना विस्तार

- ▶ **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण** — 314 राजकीय कॉलेजों में बालिका सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु।
- ▶ **राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम** — उद्योग-उन्मुख कौशल को शिक्षा से जोड़ने हेतु ₹25 करोड़ बजट प्रावधान (2024-25 घोषणा)।
- ▶ 35 कॉलेजों में ICT लैब (₹7.12 करोड़) व 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम (₹29.99 करोड़) स्वीकृत; 122 कॉलेजों में खेल सुविधाओं हेतु ₹13.05 करोड़ स्वीकृत।

तकनीकी शिक्षा — कुशल एवं नवाचारी कार्यबल का निर्माण

तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों व शिल्पों में विशिष्ट ज्ञान व कौशल से लैस करती है — जिससे राज्य की तकनीकी जनशक्ति वैश्विक मानकों तक पहुँचे।

 इंजीनियरिंग कॉलेज 73 19 राजकीय + 54 निजी; क्षमता 27,753	 MBA संस्थान 52 7 राजकीय + 45 निजी; क्षमता 4,474	 पॉलिटेक्निक कॉलेज 137 क्षमता 25,802 (तालिका 3.6 देखें)	 ITI 314 राजकीय + 1,385 निजी क्षमता क्रमशः 63,960 व 2,12,624
---	---	--	---

- ▶ राज्य में 1 IIT (जोधपुर), 1 IIIT (कोटा), 1 MNIT (जयपुर) व 1 IIM (उदयपुर) भी कार्यरत — सभी इंजीनियरिंग/प्रबंधन कॉलेज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय-कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध।

तालिका 3.6 : पॉलिटेक्निक कॉलेजों की भौतिक प्रगति

वर्ष	राजकीय कॉलेज	निजी कॉलेज	कुल कॉलेज	राजकीय क्षमता	निजी क्षमता	कुल क्षमता
2024-25	48	68	116	7,565	14,673	22,238
2025-26	69	68	137	10,994	14,808	25,802

- ▶ 56 राजकीय सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक (क्षमता 9,376), 1 केंद्र सह-शिक्षा कॉलेज (क्षमता 60) व 12 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक (क्षमता 1,558) — राजकीय कुल क्षमता 10,994। ₹105.48 करोड़ आवंटन में ₹46.35 करोड़ खर्च।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)

 **परिभाषा :** कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता (SEE) विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान जो शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान करते हैं

 **आसान भाषा में :** यानी जहाँ बच्चे 10वीं/12वीं के बाद सीधे कोई हुनर (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आदि) सीखकर सीधे नौकरी के लिए तैयार होते हैं।

 **उदाहरण :** 314 राजकीय ITI (क्षमता 63,960, जिनमें 12 महिला ITI शामिल — जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, मंडोर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर) व 1,385 निजी ITI (क्षमता 2,12,624)। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के तहत 44 इंजीनियरिंग व 35 गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में 1-2 वर्षीय प्रशिक्षण। ₹496.82 करोड़ आवंटन में ₹119.21 करोड़ खर्च।

चिकित्सा शिक्षा — स्वस्थ राज्य हेतु सुदृढीकरण

चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने, चिकित्सकों की कमी दूर करने व ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ज़रूरी है।

 कुल मेडिकल कॉलेज 49 दिसंबर 2025 तक	 कुल डेंटल कॉलेज 17 2 राजकीय + 15 निजी	 UG सीटें (सभी) 8,980 सरकारी+निजी मेडिकल-डेंटल	 PG सीटें (सभी) 3,930 +446 सुपर-स्पेशलिटी सीटें
--	---	---	--

49 मेडिकल कॉलेजों का विभाजन

- ▶ 6 राजकीय, 1 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) का संघटक कॉलेज, 24 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (RajMES) के तहत, 2 ESI कॉलेज (अलवर व जयपुर), 1 AIIMS जोधपुर, तथा शेष 15 निजी क्षेत्र में।
- ▶ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG की 4,730 (डेंटल सहित) व PG की 2,098 सीटों पर नामांकन (2025-26/2024-25)। ₹91.46 करोड़ आवंटन में ₹23.03 करोड़ खर्च।
- ▶ मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल राजस्थान के बड़ी संख्या में OPD/IPD मरीजों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों — हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश — के मरीजों का भी उपचार करते हैं।

NEW नए मेडिकल कॉलेज — चरणबद्ध विस्तार

दूसरा चरण — धौलपुर (2022-23 से); **तीसरा चरण** — श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरौही (2022-23), फिर अलवर, दौसा, करौली, बूंदी, हनुमानगढ़ (2023-24), फिर बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर (2024-25, प्रत्येक में 100 MBBS सीटें)।

2025-26 में **टोंक व जैसलमेर** में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू (प्रत्येक 50 MBBS सीटें) — कुल 15 नए कॉलेज ₹325 करोड़/कॉलेज की लागत से (केंद्र 60% : राज्य 40%); सभी की DPR स्वीकृत, निर्माण कार्य प्रगति पर।

RajMES के तहत 2025-26 में ₹3,630.50 करोड़ आवंटन में ₹1,116.95 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।

वार्षिक प्रवेश क्षमता (राजकीय संस्थान)

संस्थान	UG सीटें	PG सीटें	सुपर-स्पेशलिटी
राजकीय मेडिकल कॉलेज (कुल)	4,330	1,974	210
AIIMS जोधपुर	150	190	83
निजी मेडिकल कॉलेज (कुल)	2,800	1,398	153

- डेंटल कॉलेज — राजकीय (RUHS संघटक + जोधपुर डेंटल कॉलेज) की क्षमता 100 UG + 28 PG; निजी डेंटल कॉलेजों की क्षमता 1,450 UG + 340 PG।
- 28 ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में 8 विशेषज्ञताओं में पोस्ट-MBBS डिप्लोमा कोर्स (क्षमता 381); RUHS जयपुर (2021-22 से) तथा जोधपुर व उदयपुर (2022-23 से) में Masters in Public Health (MPH) कोर्स (क्षमता 25)।

ॐ संस्कृत शिक्षा का पुनरुद्धार

संस्कृत शिक्षा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, बौद्धिक विकास व भारत के प्राचीन साहित्य-दर्शन से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में संस्कृत हेतु अलग निदेशालय **1958** में व संस्कृत विश्वविद्यालय **1998** में स्थापित हुआ — दोनों ही देश में अग्रणी पहल थीं।

तालिका 3.7 : राजस्थान में संस्कृत शिक्षा संस्थान (2025-26)

स्तर	राजकीय	निजी	कुल
कुल संस्कृत शिक्षा संस्थान	1,872	502	2,374

- इन 2,374 संस्थानों में **1.56 लाख विद्यार्थी** अध्ययनरत; 1 राजकीय + 15 निजी STC कॉलेज तथा 1 राजकीय SSIERT + 82 निजी शिक्षा शास्त्री कॉलेज कार्यरत। ₹290.70 करोड़ प्रावधान में ₹196.94 करोड़ खर्च (दिसंबर तक)।

SSSIERT, महापुरा (जयपुर)

राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान — कक्षा 1-12 तक संस्कृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें व प्रशिक्षण सामग्री तैयार करता है; संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण व संस्कृत को "जनभाषा" बनाने के प्रयास भी करता है।

2025-26 में ₹94 लाख प्रावधान में ₹57.43 लाख खर्च — 2,551 शिक्षक लाभान्वित।

भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने व सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए स्थापित है।

 कुल पुस्तकालय 323 1 राज्य केंद्रीय + 7 संभागीय + 33 ज़िला + 282 पंचायत समिति स्तर	 कुल पुस्तकें 22,87,985 47 विभागीय पुस्तकालयों में	 नए सदस्य (2025-26) 14,289 पंजीकृत
--	---	---

- ▶ भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को 2025-26 में ₹479.54 लाख आवंटन में से ₹262.22 लाख व्यय हुआ (दिसंबर तक) — यह राशि पुस्तकालय भवन, संसाधन व संचालन पर खर्च होती है।
- ▶ चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, बाल-कॉर्नर, महात्मा गाँधी कॉर्नर, नवसाक्षर कॉर्नर व दृष्टिबाधित पाठकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध।
- ▶ **राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर** — देश के सरकारी पुस्तकालयों में पहली बार RFID (Radio Frequency Identification) प्रणाली लागू, जिससे पुस्तक लेन-देन आसान व कम स्टाफ में संचालन संभव हुआ।
- ▶ **सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र** — 33 ज़िला पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु, प्रत्येक केंद्र पर मार्गदर्शक उपलब्ध; ₹93.06 लाख आवंटन में ₹46.53 लाख खर्च।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — प्रगतिशील राज्य की दिशा में

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्थापना 1983, मुख्यालय जयपुर) प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं व सेमिनारों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाता है तथा STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्रों में करियर हेतु प्रोत्साहित करता है।

- ▶ 4 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ **जोधपुर व उदयपुर में डिजिटल तारामंडल** निर्माण हेतु समझौता (प्रत्येक ₹13 करोड़, संस्कृति मंत्रालय व राज्य विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में)। ₹32.05 करोड़ आवंटन में ₹11.94 करोड़ खर्च।
- ▶ **राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र (SRSAC), जोधपुर** — मिट्टी, जल, वन, कृषि व खनिज मानचित्रण के ज़रिए विकास योजना में सहयोग; जयपुर के इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान में उप-केंद्र स्थापित।
- ▶ **अनुसंधान एवं विकास प्रभाग** — वैज्ञानिक व गैर-सरकारी शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता; कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर में नए विज्ञान केंद्र, डिजिटल तारामंडल व इनोवेशन हब निर्माणाधीन।
- ▶ **पेटेंट सूचना केंद्र (PIC), जयपुर** — बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) जागरूकता व पेटेंट फाइलिंग सहायता।

KARYA कार्यक्रम

 **परिभाषा** : Knowledge Augmentation through Research in Young Aspirants — विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शोध संस्थानों में इंटरनशिप व अनुसंधान प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप कार्यक्रम

 **आसान भाषा में** : यानी विज्ञान पढ़ने वाले होनहार छात्रों को बड़े शोध संस्थानों में जाकर असली रिसर्च का अनुभव लेने के लिए स्कॉलरशिप।

 **उदाहरण** : KARYA-2025 के तहत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई।

2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी 2025) पर राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार — ग्रासरूट इनोवेशन व उच्च शिक्षण संस्थान श्रेणी में प्रथम ₹1 लाख, द्वितीय ₹51,000, तृतीय ₹21,000।

जयपुर के इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान में SRSAC उप-केंद्र स्थापित।

2025-26 में एस्ट्रो नाइट टूरिज्म गतिविधि के तहत विज्ञान केंद्र, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल जैसे 5 स्थानों पर कार्यक्रम — लगभग 1,600 प्रतिभागियों ने आकाश-दर्शन किया।

मुख्य परीक्षा दृष्टि से — अध्याय का सार (विश्लेषण)

नींव से शिखर तक का मॉडल — राजस्थान की शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा (नींव), उच्च व तकनीकी शिक्षा (कौशल), और चिकित्सा-संस्कृत-विज्ञान शिक्षा (विशेषज्ञता) को एक सतत श्रृंखला के रूप में जोड़ती है — हर स्तर पिछले स्तर पर आधारित है।

आँकड़े बनाम गुणवत्ता का अंतर — GER व PTR जैसे सुविधा-संकेतक राष्ट्रीय सिफारिश से बेहतर हैं, पर माध्यमिक स्तर पर ठहराव दर में गिरावट (59.1%→55.9%) दिखाती है कि पहुँच बढ़ने के बावजूद कक्षा 9-10 पर बच्चों को टिकाए रखना अब भी चुनौती है — यह "क्वांटिटी बनाम क्वालिटी" के अंतर को उजागर करता है।

केंद्र-राज्य भागीदारी मॉडल — अधिकांश प्रमुख योजनाएँ (समग्र शिक्षा, PM Usha, PM SHRI, नई मेडिकल कॉलेज) 60:40 फंडिंग पैटर्न पर आधारित हैं, जो राज्य की सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े पैमाने पर अवसंरचना विस्तार को संभव बनाती है।

बालिका-केंद्रित डिज़ाइन एक सतत थीम — KGBV, लाडो प्रोत्साहन, कालीबाई भील स्कूटी, देवनारायण स्कूटी, बालिका दूरस्थ शिक्षा जैसी अनेक योजनाएँ स्कूल से उच्च शिक्षा तक बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर घटाने व नामांकन बढ़ाने की सुसंगत रणनीति दर्शाती हैं।